>

Title: Need to include a column for caste, particularly OBC in the Census, 2011.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन के सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार पिछड़ों के विकास पर ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। भारत सरकार नहीं चाहती है कि देश की विचारधारा में जो जातियाँ पीछे रह गई हैं, उनका विकास किया जाए। देश में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसकी गणना किये जाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया पर सरकार ने आज तक पिछड़े वर्गों की गणना नहीं कराई। 2011 के लिए जो गणना किये जाने का कार्य 1 अप्रैल 2010 से शुरू किया गया है, उसमें सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि देश में जातिगत जनगणना की जाएगी, परंतु सरकार के कुछ मंत्रियों ने इस जाति आधारित जनगणना के विरोध में पत्र लिखे हैं और कई मंत्रिगण इसका अंदर से विरोध कर रहे हैं। सरकार इस संबंध में इस तरह का नाटक कर रही है, मंत्रिगण इसका मामला कैबिनेट में भेज रहे हैं, कभी कोई कमेटी बना रहे हैं, और उन्होंने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर राय मांगी है कि इसे लागू किया जाए या नहीं। जब सदन ने इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया है तो इसको अमल में लाना सरकार की नैतिक एवं संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।

महोदय, देश में कितनी महिलाएँ ओबीसी हैं, इसकी जानकारी भी सरकार के पास नहीं है। केन्द्रीय विधि मंत्री एम.वीरप्पा मोइली ने महिला आरक्षण विधेयक पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण मानने से इंकार किया है और राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1931 के बाद से अब तक ओबीसी की कोई गणना नहीं हुई है। इसलिए जब तक ये आँकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक यह फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन ओबीसी है और कौन ओबीसी नहीं है। इससे साफ हो गया है कि भारत सरकार की मंशा ओबीसी के कल्याण की नहीं है। केवल ओबीसी की योजनाओं का नाम लेकर वह ढोंग रचती है। देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए स्थापित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ओबीसी यूनिट में सात आदमी काम करते हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी मांग रखिये।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल : बिना उनकी जनसंख्या का पता लगाए कौन सा कल्याण कार्य ओबीसी का हो रहा है? ओबीसी का विकास यूपीए सरकार के एजेन्डा में नहीं है। जब 2011 जनगणना में जातियों का पता लगाया जा रहा है तो जातियों का कॉलम क्यों नहीं है? क्या ओबीसी की इस राष्ट्र के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है? स्कूल कालेजों में जातियों का उल्लेख हो रहा है, सरकारी कार्यालयों में जाति प्रमाण-पत्र जारी हो रहे हैं, दूसरी ओर सरकार कहती है कि ओबीसी की गणना से जाति-विद्वेष फैलेगा। क्या जनगणना में जातियों के उल्लेख से जाति-विद्वेष नहीं फैलेगा? मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जब सदन में 2011 से शुरू होने वाली जनगणना के लिए जाति के आधार पर जनगणना का प्रस्ताव पास किया है एवं सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है तो 2011 से शुरू होने वाली जनगणना के लिए जो प्रयोग किये जा रहे हैं, उसमें जाति का कालम क्यों नहीं है? इसे पास कर दिया जाए और इसे लागू किया जाए।

सभापति महोदय :

श्री हुक्मदेव नारायण यादव,

श्री भूदेव चौधरी एवं

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो के नाम श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।